छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली

छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का सातवाँ वार्षिक सम्मेलन

आयोजक

शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

आयोजन दिनांक 2 तथा 3 फरवरी 2015

प्रतिवेदन

प्रायोजक – स्वशासी प्रकोष्ठ शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर

Scanned by CamScanner

शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय राजनांदगांव द्वारा, छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का सातवाँ वार्षिक सम्मेलन दिनांक 2 तथा 3 फरवरी 2015 को आयोजित किया गया। मुख्य विषय "छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली" था। जिसके अन्तर्गत छ.ग. में कृषि से संबंधित बिन्दु (1) कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता (2) कृषि उत्पादन हेतु उपलब्ध संसाधन (3) कृषि उपज मण्डी (4) कृषि उत्पादन हेतु शासकीय नीतियाँ (5) कृषि वित्त व्यवस्था (6) कृषि बीमा योजना (7) कृषि बजट (8) कृषि वित्त एवं नाबार्ड (9) कृषि सुधार एवं विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा से संबंधित बिन्दुओं – (1) खाद्य सुरक्षा एवं भण्डारण व्यवस्था (2) मुख्यमंत्री खाद्य योजना (3) खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत पोषाहार कार्यक्रम (4) कृषि उपज भण्डारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित बिन्दुओं (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबी निवारण (2) सार्वजनिक विरतण प्रणाली की स्थिाति, चुनौतियाँ एवं संभावना (3) हितग्राही चयन– आदि पर शोध पत्र तथा आलेख प्रस्तुत किये गये ।

दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन दिनांक 2 फरवरी 2015 को प्रातः 10.30 बजे महाविद्यालय के बख्शी सभागार में आयोजित किया गया । इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि डॉ. डी.एस. मिश्रा अतिरिक्त सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार ठाकुर सचिव भारतीय आर्थिक परिषद थे। डॉ. हनुमन्त यादव अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद विशिष्ट वक्ता के रूप में मंचासीन थे।

मुख्य अतिथि डॉ. डी.एन. मिश्रा ने विषय पर अपना विशेष व्याख्यान दिया। अपने उद्बोधन में कहा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, तथा दार्शनिक प्लूटो एवं अरस्तू का अध्ययन मनुष्य की "भोजन के हक" की व्याख्या करता आया है। इसी तरह मार्क्स से लेकर अमर्स्य सेन तक सभी के विचार इसी बात को इंगित करते हैं कि मनुष्य का भोजन पर हक है। अर्थशास्त्र के श्रम विभाजन अधिकतम लाभ जैसे सिद्धान्तों के साथ ही साथ जब नैतिक अभिप्रेरणा तथा विकास का प्रयास संयुक्त रूप से होता है तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छाशक्ति ही उसे उसके रोटी पाने के अधिकार तक पंहुचा सकती है। इसके लिये आवश्यक है कि प्रशासनिक स्तर पर, लोगों तक भोजन पंहुचाने का प्रभावी तरीका विकसित हो तथा इसे क्रियान्वित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो। यह कार्य सभी के साझा प्रयास एवं समंवय से ही संभव हो सकता है । यदि यह धरातलीय स्तर पर सच्चाई से लागू हो सके तभी संभव है कि भारत को भूख से पीड़ित विश्व के पन्द्रह देशों की सूची से बाहर निकाला जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का सम्मेलन शुरू, वक्ताओं ने कहा कि अधिकारों की रक्षा के लिए बनें जागरुक

राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी

संबोधन वक्ताओं ने अधिकांश विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।

राजनांदगांव bureau@patrika.com शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का दो दिवसीय सातवां वार्षिक सम्मेलन सोमवार को शुरू हुआ। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

यह सम्मेलन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित और स्वशासी प्रकोष्ठ तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रायोजित है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त सचिव डीएस मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना का सुमधुर गान किया।

धरती पर जिसने जन्म लिया, भोजन पर उसका अधिकार

मुख्य अतिथि मिश्रा ने एक प्रेजेंटेशन राइट टू फूड एवं न्यूट्रिशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, भोजन के अधिकार जैसे मुद्दे पर प्रकाश डाला। प्रख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, अमर्त्य सेन आदि के विचारों का उल्लेख करते हुए समझाया कि इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, भोजन पर उसका अधिकार है। सवाल है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावशाली क्रियान्वयन से इस अधिकार की रक्षा कैसे की जाए। दूसरे वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

अध्यक्षता भारतीय आर्थिक परिषद् के सचिव डॉ अनिल कुमार ठाकुर ने की।

विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद् के अध्यक्ष डॉ हनुमन्त यादव, अर्थशास्त्री, कलेक्टर अशोक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक डॉ संजीव शुक्ला तथा जिला पंचायत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला थीं।

हर संभव कोशिश

प्रारंभ में प्राचार्य डॉ. आरएन सिंह ने स्वागत उद्बोधन में महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र परिषद् में सम्मेलन से शोध तथा आर्थिक विकास को नई दिशा मिले, ऐसी हर संभव कोशिश की जाएगी। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉ. सिंह, डॉ चन्द्रिका नाथवानी, डॉ मीना प्रसाद, डॉ सुमीता श्रीवास्तव कु. ख्याती अग्रवाल आदि ने किया। इस अवसर पर सम्मेलन की संक्षेपिका का विमोचन मुख्य अतिथि ने किया।

डॉ. हनुमन्त यादव ने अपने विशिष्ट वक्तव्य में कहा कि प्रदेश में कृषकों की उन्नति तभी संभव है जब इस दिशा में शोध हो । आपने कहा कि कृषि, उत्पादकता तथा खाद्य सुरक्षा जैसी ज्वलन्त समस्याओं का हल बिना जमीनी अध्ययन के संभव नही है। राज्य में भूमि का अपखण्डन बढ रहा है जिसका प्रभाव असिचिंत सीमान्त कृषि जोतों की घटती संख्या के रूप में हमारे सामने है फलतः अधिकांश कृषि जोते अनार्थिक होती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में सहकारी एवं सामूहिक कृषि को बढावा दिया जाये, इससे कृषकों को व्यक्तिगत कर्जों तथा संभावित नुकसान से भी छुटकारा मिल सकेगा। प्रदेश में कृषक वर्ग के मध्य एक बात धीरे–धीरे बढ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्सव के समय अपव्यय के कारण कृषक कर्ज में दबता जा रहा है । यह सब रोका जाना चाहिये । आज के युवा वर्ग व शोधार्थी का दायित्व है कि वह छत्तीसगढ की कृषि के संबंध में शोध करें ताकि यह बात सामने आये कि किस तरह कृषि उत्पादन व उत्पादकता को बढाकर प्रदेश की कृषि को उन्नत किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

हर जन्म लेने वाले का भोजन पर होता है अधिकारः डा. मिश्रा

राजनांदगांव। दिग्विजय महाविद्यालय में सोमवार को छग आर्थिक परिषद् का 7 वां दो दिवसीय सम्मेलन शुरुआत हुई, सम्मेलन में मुख्य अतिथि वित्त व योजना विभाग के अतिरिक्त सचिव डा. डीएन मिश्रा थे। अध्यक्षता भारतीय आर्थिक परिषद् के सचिव डा. अनिल कुमार ठाकुर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में छग आर्थिक परिषद् के अध्यक्ष डा. हनुमंत यादव, कलेक्टर अशोक अग्रवाल, एसपी डा. संजीव शुक्ला व जिपं सीईओ डा. प्रियंका शुक्ला उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद संस्था के छात्राओं ने सरस्वती वंदना की सुमधुर गान की प्रस्तुति दी। सम्मेलन में छग में कृषि, खाद्य सुरक्षा व सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डा. मिश्रा ने कहा कि भोजन हक के लिए जरूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्होंने राइट टू फूड व न्यूट्रिशन के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा भोजन के अधिकारी जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। डा. मिश्रा ने अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, प्लेटो, अरस्तू, मार्क्स, अमर्त्य सेन आदि के विचारों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, भोजन पर उसका अधिकार है। सवाल है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावशाली क्रियान्वयन से इस अधिकार की रक्षा कैसे किया जाए।

एकजुट होकर करना होगा काम

सम्मेलन में डा. मिश्रा ने अर्थशास्त्र के श्रम विभाजन, अधिकतम लाभ जैसे सिद्धांतों के अलावा नैतिक अभिप्रेरण व साझा प्रयासों की अहमियत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भोजन का अधिकार सबके समझदार सहयोग और समन्वय से ही परवान चढ़ सकता है। भारत को दुनिया में भूख से सबसे ज्यादा त्रस्त पंद्रह देशों की फेहरिस्त से बाहर निकालने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। भोजन की उपलब्धता उस तक पहुंच और उसकी पर्याप्तता में ही भोजन के अधिकार की सार्थकता है।

कार्यक्रम के दौरान संक्षेपिका पुस्तक का विमोचन किया गया।

आत्महत्या पर लगानी होगी रोक

सम्मेलन में अर्थशास्त्री परिषद् के प्रांतीय अध्यक्ष हनुमंत यादव ने कहा कि छग में आत्महत्या के कारणों पर रोक लगाना होगा। इस विषय पर उन्होंने सारगर्भित चर्चा की। उन्होंने शोधार्थियों को इस दिशा में काम करने का आव्हान किया। डा ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर आर्थिक परिषद् का महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और निराकरण करना है। उन्होंने परिषद् के जर्नल के प्रकाशन के लिए 50 हजार रुपए के आरंभिक अनुदान की घोषणा भी की।

सम्मेलन में उपस्थित परिषद के पदाधिकारी व सदस्य।

संक्षेपिका का विमोचन

सम्मेलन में मुख्यअतिथि द्वारा सम्मेलन की संक्षेपिका का विमोचन किया गया। इस दौरान प्राचार्य डा. आरएन सिंह ने कहा कि अर्थशास्त्र परिषद् में सम्मेलन से शोध व आर्थिक विकास को नई दिशा मिले, ऐसी हर संभव कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन डा. [illegible] व डा रविन्द्र ब्रम्हे ने किया।

अध्यक्षीय उद्‌बोधन में डॉ. अनिल ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रदेश की कृषि वहाँ की खाद्य आपूर्ति की रीढ होती है। छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है। ऐसे प्रदेश की कृषि को उन्नत करने, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी तक पहुंचाने का दायित्व इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से तथा शोध द्वारा सही दिशा निर्देश का है, ताकि अध्ययन से प्राप्त सुझाव एंव नीतियाँ समस्या के निराकरण की दिशा में सहयोगी हो सकेगें।

दिनांक 2 फरवरी 2015 को आयोजित तकनीकि सत्र की अध्यक्षता डॉ. अमरकान्त पाण्डे प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने की तथा विशिष्टवक्ता डॉ. के.सी. जैन सेवानिवृत प्राध्यापक अर्थशास्त्र डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर उपस्थित थे। इस सत्र में करीब 12 शोध पत्रों का वाचन किया गया। प्रस्तुत शोध पत्रों तथा इन पर हुई चर्चा के माध्यम से यह बात सामने आई कि कृषि की उन्नति तथा विकास तभी संभव है जब सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी कृषकों को मिले साथ ही इन योजनाओं का संचालन भी सही तरीके से हो ताकि कृषकों को इसका उचित लाभ प्राप्त हो सके। इसका परिणाम यह होगा कि कृषकों का शासन पर विश्वास बढेगा तथा उनका शासन से समन्वय भी बना रहेगा। छत्तीसगढ़ की कृषि में एक बात यह भी देखने मिलती है कि यहाँ महिलाओं का कृषि कार्य में बडा योगदान है, अतःयह आवश्यक है

Scanned by CamScanner

सत्र के अन्त में अपने विशिष्ट वक्तव्य में डॉ.के.सी. जैन ने कहा कि छ.ग. में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त है कृषको की स्थिति में सुधार की चर्चा करते हुए आपने कहा कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है ताकि कृषक द्वितथा त्री फसल चक्र पर कार्य कर सकें। कृषकों को पर्याप्त सुविधा देकर तथा उनकी समस्या के निराकरण से ही कृषि उत्पादकता बढाई जा सकती है। भू–सुधार कार्यक्रम की भी चर्चा की तथा माना कि अपखण्डन को रोका जाना चाहिए ताकि उन्नत प्रौद्योगिकी लागू हो। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को प्रदेश की गरीब जनता के लिये महत्वपूर्ण माना तथा इस दिशा में सरकार की भूमिका व कार्य के और अधिक विस्तार पर बल दिया । तकनीकि सत्र की समाप्ति पर अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में डॉ.ए. के. पाण्डे ने कहा कि सत्र में प्रस्तुत विभिन्न शोध पत्रों तथा चर्चा से निष्कर्षतः यह बात सामने आती है कि प्रदेश की कृषि का विस्तार तथा खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्‌दों में सुधार हेतु समाज के सहयोग व प्रयास की आवश्यकता है ताकि सरकारी स्तर की योजनाओं की सफलता संभव हो सके।

सम्मेलन के दूसरे दिन दिनांक 3 फरवरी 2015 को प्रातः कालीन सत्र में अध्यक्षता डॉ. पी.राघवन पूर्व कृषि सचिव छ.ग. शासन ने की । इस सत्र में श्री जी. सरजियस मिंज – मुख्य सूचना आयुक्त छ.ग. शासन ने विशिष्ट उद्‌बोधन दिया। इस सत्र में शोधार्थियों ने भी अपने शोध आलेख प्रस्तुत किये – जो कृषि योजना, कृषि उपज मण्डी, कृषि वित्त व्यवस्था तथा कृषि बीमा योजना, मुख्यमंत्री खाद्य योजना, पोषाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी निवारण आदि पर केन्द्रित थे।

Scanned by CamScanner

कि भू–स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जावे। इसके साथ ही महिलाओं की शिक्षा, कृषि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था शासन स्तर पर निः शुल्क होनी चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने की बात सामने आई। प्रदेश में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिये वित्तीय सुविधाओं का विस्तार हो तथा आसान ऋण नीति की व्यवस्था पर बल दिया जाये। प्राप्त कृषि उत्पादन की विपणन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की चर्चा की गई ताकि कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले यद्यपि सरकार समर्थन मूल्य के माध्यम से कृषि विपणन का कार्य करती है किन्तु इसमें और सुधार की आवश्यकता की बात की गई।

प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों के लिये उचित विपणन एवं बाजार की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । कृषि के साथ–साथ कृषि सहायक उद्योगों के विकास को भी बढावा दिया जाना चाहिये ताकि श्रम पलायन की समस्या को कम किया जा सके। कृषि हेतु सरकार की सिंचाई योजना, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन आदि को प्रदेश की कृषि हेतु सरकार का सराहनीय कदम माना साथ ही साथ प्रदेश के बजट में कृषि हेतु विशेष प्रावधान को कृषक वर्ग के हित के रूप में निरूपित किया गया।

कृषि उन्नति तथा उत्पादन प्राप्ति की सार्थकता उसके उचित भण्डारण तथा सुरक्षा में है। इस पर प्रस्तुत शोध पत्रों द्वारा यह बात सामने आई कि खाद्यान्न की उपलब्धता तथा खाद्य पदार्थों तक पहुंच को आसान बनाना चाहिये । प्रदेश में उचित तथा पर्याप्त भण्डारण के अभाव के कारण प्रतिवर्ष खुले में खाद्यान्न रखा जाता है उसके कारण खाद्यान्न की क्षति होती है। इस दिशा में कारगार कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को प्रदेश में भण्डारण की व्यवस्था हेतु भण्डारगृहों (FCI के गोदामों का निर्माण) के निर्माण को बढावा देना चाहिये। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश की गरीब जनता तक उचित पोषाहार को पंहुचाने पर भी चर्चा हुई ताकि उन्हें भोजन के आवश्यकत घटक प्राप्त हो सके जो स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

Scanned by CamScanner

श्री मिंज ने कृषि क्षेत्र को आजीविका का मुख्य स्त्रोत बताया तथा कहा कि जब तक छोटे तथा सीमान्त कृषकों की समस्या को समझ कर उसके अनुकूल योजनाएँ नहीं बनेंगी तब तक कृषि की उत्पादकता को तेजी से बढाना संभव नही होगा । भारत में कृषि ही देश की मुख्य आत्मा तथा किसान इस देश का गौरव है। कृषकों को यदि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो तो इससे एक तरफ तो वर्ष भर कृषि कार्य करना संभव होगा साथ ही साथ सर्वाधिक रोजगार भी इस क्षेत्र में बढेगा, इस प्रकार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कृषक वर्ग तथा गाँवों को कई गुना लाभ दे सकती है। जब देश का कृषक उन्नत, समृद्ध, सुखी तथा खुशहाल होगा उसी स्थिति में देश भी उन्नत तथा समृद्ध बन सकेगा। देश में आजादी के बाद बनाई गई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि तथा कृषकों की उन्नति के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का ही यह प्रमाण है कि आज भारत में कृषि उन्नत हुई है देश खाद्यान्न के संबंध में आत्म निर्भर बन सका है।

दैनिक दावा

संस्कारधानी

किसानों की खुशी पर निर्भर है देश का विकासः मिंज

0 समाज के साझा सहयोग से समावेशी विकास संभव : प्रो. ज्ञानप्रकाश

0 छग. आर्थिक परिषद् के सम्मेलन में हुए प्रभावी तकनीकी सत्र

निगम में कथि

Scanned by CamScanner

किसानों पर निर्भर देश का विकास: मिंज

भास्कर न्यूज | राजनांदगांव

कृषि भारत की आत्मा, किसान देश का गौरव और सिंचाई वह साधन है, जिससे सर्वाधिक रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। देश के विकास के लिए हमें सबसे पहले किसानों पर ही फोकस करना होगा। जिस देश का किसान सुखी रहेगा, उसका भाग्योदय सुनिश्चित है।

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सरजियस मिंज ने दिग्विजय कॉलेज में आयोजित छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद के सम्मेलन के दूसरे दिन हुए तकनीकी सत्र में ये बातें कहीं। मिंज ने कहा जब हम कृषि क्षेत्र को आजीविका के रूप में देखें तो हमारा ध्यान छोटे और सीमांत किसानों की तरफ जाना चाहिए। आजादी के बाद हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि और किसानों की प्रगति के लिए लगातार कार्यक्रम चले हैं। यह क्रम आज भी निरंतर है, किंतु हमारी कोशिशों को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और परिणाम मूलक बनाना सबसे अहम जरूरत है। प्रथम वक्ता पूर्व कृषि सचिव पी राघवन ने किसानों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की देखरेख पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए। डॉ. चन्द्र कुमार जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का यह सम्मेलन विचारों की ऊर्जा तथा सुझावों की पारदर्शिता की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

दिग्विजय कॉलेज में आर्थिक परिषद के सम्मेलन में मौजूद अतिथि व प्रोफेसर।

डॉ. पी. राघवन ने लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिये महत्वपूर्ण निरूपित किया। आपने कहा कि जापान की तरह कृषि पद्धति अपनाई जाना चाहिये। छ.ग. में उपलब्ध पडती भूमि (बंजर भूमि) पर कृषि उत्पादन करने हेतु शोध की आवश्यकता है इससे कृषि भूमि क्षेत्रफल का विस्तार होगा तथा कृषि उत्पादन बढाया जा सकेगा। सिंचाई की आवश्यकता के संबंध में कहा कि वर्षाकालीन जल का संग्रहण किया जाना चाहिये। यह कार्य बडे बांध के साथ छोटे तथा मध्यम बांध बनाकर किया जा सकता है लघु तथा सीमान्त कृषकों को इन सिंचाई योजनाओं से जल आपूर्ति संभव होगी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। हार्टिकल्चर की चर्चा करते हुए आपने इसे कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने का एक माध्यम निरूपित किया। किसानों तथा कृषि वृद्धि हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की उचित देखरेख तथा इसका सही दिशा में क्रियान्वयन करके ही कृषि को सही दिशा प्रदान करना संभव होगा ।

Scanned by CamScanner

अपरान्ह के तकनीकि सत्र की अध्यक्षता श्री दिनकर केशव भाकरे जी ने की तथा इस सत्र में डॉ. ज्ञान प्रकाश प्राध्यापक अर्थशास्त्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर ने विशिष्ट वक्तव्य दिया। इस सत्र में शोध पत्रों का वाचन भी किया गया । डॉ. ज्ञान प्रकाश ने अपने वक्तव्य में कहा कि कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता को कम किया जाना आवश्यक है। भू–सुधार कानून लागू करके भारतीय कृषि को उन्नत करना संभव होगा। कृषि उन्नति के कार्यक्रम बनाने मात्र से कृषि की उन्नति नही हो सकती। आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन हो तथा समय–समय पर उसकी समीक्षा भी की जावे। कृषि की उन्नति तथा खाद्य सुरक्षा के माध्यम से गरीबों तक रोजगार तथा खाद्यान्न की पंहुच संभव होगी। इसके लिये आवश्यक है कि कृषकों के बीच जाकर समस्या का आकलन हो उसे समझा जाये तथा सही समाधान व योजना बनाई जाये।

कृषि तथा खेती किसानी किसी देश की जीवन रेखा की तरह है जो तभी जीवित रहेगी जब भूमि व्यवस्था, जल प्रबंन्धन, अंधोसरंचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नति का विस्तार हो यह सब कृषि क्षेत्र में निरन्तर शोध से संभव है । कृषि बाजार व्यवस्था का नेटवर्क भी विस्तृत करना आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके ही विभिन्न चुनौतियों का सामना करना संभव है और यही समस्या का समाधान भी है। कृषि की उन्नति से समावेशी विकास आगे बढेगा। इसके लिये शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना होगा, ये सभी समावेशी विकास के मार्ग को आगे बढायेगें। जब तक सरकार व समाज का साझा प्रयास तथा सहयोग नही होता तब तक समावेशी विकास संभव नही है।

कृषि भारत की आत्मा, किसान देश का गौरव

अध्यक्षीय उद्‌बोधन में भाकरे जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारतीय जीवन पद्धति की एक परंपरा निरूपित किया। आपने कहा कि गाँवों में कृषि कार्य के साथ–साथ पशु पालन को कृषि सहायक व्यवसाय के रूप में बढावा देना होगा। यह गाँवों के विकास तथा गाँवों में रोजगार सृजन के लिये आज की आवश्यकता तथा अनिवार्यता है।

Scanned by CamScanner

सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉ. आर.एन.सिंह प्राचार्य शास. दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव ने कहा कि छ.ग. में कृषि विकास की असीम संभावनाएँ हैं। यहाँ फसल विविधीकरण लागू किया जाना चाहिए । सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का ही परिणाम है कि विगत एक दशक में अनाज, दलहन व तिलहन का उत्पादन बढा है। छत्तीगसढ़ प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा कानून लागू किया है साथ ही यहाँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 11045 उचित मूल्य की दुकाने संचालित की जा रही है।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि श्री दिनकर केशव भाकरे तथा अध्यक्षता श्री सत्यनारायण अग्रवाल ने की । मुख्य अतिथि ने इस तरह के सम्मेलन को आज के शोध–परक समय की आवश्यकता बताया तथा कहा कि इस तरह के आयोजन से शोधार्थियों को अवसर प्राप्त होते है। छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद के सचिव डॉ. रविन्द्र ब्रह्में प्राध्यापक अर्थशास्त्र अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर ने दो दिवसीय सम्मेलन में प्रस्तुत शोध आलेखों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सम्मेलन में पढे गये शोध पत्रों तथा विषय विशेषज्ञों के विशिष्ट व्याख्यान से यह बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ में कृषि को लाभदायक बनाने तथा इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिये उचित नीति की आवश्यकता है। प्रदेश में कृषि हेतु उपलब्ध मिट्टी तथा जलवायु परिवर्तन आधारित क्षेत्रीय शोध को बढावा दिया जाना चाहिये। जब कृषि विकसित होगी तभी द्वितीयक क्षेत्र तथा सहयोगी क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्पादन तथा उत्पादकता के अन्तर का कारण कृषि क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश में भारी अन्तर का होना है इस स्थिति को सुधारना होगा इसके लिये, सिंचाई, उर्वरक उन्नत बीज, कृषि यंत्र, भूमि प्रयोग आदि में बदलाव आवश्यक है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों को उचित पोषाहार की जानकारी दी जानी चाहिये । उचित भण्डरण व्यवस्था को बढावा दिया जावे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि सही हाथों तक अनाज व अन्य आवश्यक वस्तुएँ पहुंच सके।

Scanned by CamScanner

दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से आये प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों व आलेखों से ही विषय से संबंधित, मंथन द्वारा नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। आयोजक महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष तथा सम्मेलन की संयोजक डॉ. चन्द्रिका नाथवानी विभाग की डॉ.(श्रीमती) सुमीता श्रीवास्तव सहायक

4

छग आर्थिक परिषद के सम्मेलन का समापन

राजनांदगांव। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद का दो दिवसीय सातवां सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। दूसरे दिन आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य एवं आयोजन संरक्षक डॉ. आर.एन.सिंह ने की। प्रमुख वक्ता प्रो. जे. एन.भारद्वाज, डॉ. अमिताभ पण्डा, आयुक्त सांख्यिकी, छ.ग. शासन थे।

आयोजन के मीडिया संयोजक डॉ. चन्द्रकुमार जैन ने बताया कि तकनीकी सत्र में अतिथि, वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के लोक-कल्याणकारी पक्षों पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि जरूरत मंद लोगों तक खाद्यान्न और रोजगार की पहुंच में ही विकास योजनाओं की सार्थकता है।

संगोष्ठी के समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. सत्यनारायण अग्रवाल थे। अध्यक्षता प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. हनुमन्त यादव ने की। विशिष्ट अतिथि डॉ. केवलचंद जैन, डॉ. आर. वाय मोहरे तथा पार्षद व जनभागीदारी सदस्य श्रीमती रेणु शर्मा थी। सभी अतिथियों ने सम्मेलन में विषय- विशेषज्ञों के विचार तथा शोध पत्र प्रस्तुतकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्हें मील का पत्थर निरुपित किया। समापन प्रसंग पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए। विभागाध्यक्ष डॉ. चन्द्रिका नाथवानी ने आभार व्यक्त किया।

प्राध्यापक तथा आयोजन सचिव, श्रीमती मीना प्रसाद सहायक प्राध्यापक तथा कोषाध्यक्ष के साथ ही के सभी अतिथि व्याख्याताओं, महाविद्यालय के शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टाफ, एम.ए. अर्थशास्त्र तथा एम.ए. ग्रामीण विकास के विद्यार्थियों की उपस्थिति ने सम्मेलन को सफल बनाया ।

Scanned by CamScanner